प्रेसनोट

पिथौरागढ़–11.11.13(सूवि),

स्थानीय लोगों की हकहकूक, आजीविका एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विकास को आगे बढ़ाया जाय और इसमें मुख्यरूप से वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण का संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाय। उक्त बात आज भारतीय वन संस्थान देहरादून से आये डा.प्रदीप कुमार माथुर ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित ''कैलाश पावन परिदृष्य संरक्षण एवं विकास की पहल'' बिषय पर दो दिनी कार्यशाला में बोलते हुए कही।

उन्होंने कहा कि माउन्ट कैलाश को मध्य में रखते हुए नेपाल–चीन से लगी सीमा पर वन्यजीव, नदी, चरागाह, तालाब, झील, ग्लेशियरों को सुरक्षा प्रदान करने के 2009 में भारतीय वन संस्थान के साथ नेपाल की ईसी मोड संस्थान, भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, कोसी कटारमल अल्मोड़ा द्वारा जापान के सहयोग से पहल की गई है, जिसमें सभी संबंधित विभागों का सहयोग लेकर अब इस योजना को क्रियान्वित करने की पहल की जा रही है जिसमें जनपद में स्थापित लगभग 17 हजार वन पंचायतों का भी सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने लैण्डस्केप एप्रोच और उसके चेलेंज के बारे में भी आयोजित कार्यशाला में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभाग को अन्य संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, संबंधित विभागों द्वारा भी सहयोग देना होगा साथ ही वन पंचायतों को और अधिकार सम्पन्न बनाने के साथ उन्हें संसाधन भी मुहय्या कराने होंगे जिसमें सभी की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी।

कार्यशाला को गो.ब.प.हि.वि.संस्थान अल्मोड़ा के पूर्व निदेशक डा.एल.एम.एस. पालनी ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण एवं वन पंचायत संरक्षण में लगे सभी लोगों को एक मंच में आकर वन्यजीव संरक्षण के बारे में सोच विकसित कर सम्मलित प्रयास कर कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के साथ प्रजाति, वनस्पति, वन्यजीव, ग्लेशियर, झील, तालाब आदि का संरक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के विकास से जंगलों, वन्य प्राणियों आदि पर दवाब कम होगा और उन्हें उचित संरक्षण भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वन्यजीव, जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मानव की आमद कम करके भी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए संरक्षण और विकास में संतुलन बनाये रखना होगा।

अपर जिलाधिकारी बीएल राणा ने कहा कि विकास में संतुलन से ही वन्य जीव प्राणियों के साथ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध धरोहरों के रूप में सैकड़ों सालों से मानव को जीवन देने वाली नदियों, ग्लेशियरों, तालाबों आदि का संरक्षित रखा जा सकेगा, इसमें संबंधित सभी विभागों की सहभागिता भी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय लोगों की आजीविका के संसाधनों को दूसरे रूप में भी खोजना होगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए नरेश कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में लगे लोगों के साथ विभागीय समन्वय भी इसके लिए आवश्यकीय है तथा स्थानीय लोगों के हकहकूक को भी समझना होगा और विकास की गति पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बढ़ानी होगी। कार्यशाला में बोलते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ए.के.उपाध्याय ने कहा कि स्थानीय लोगों की आजीविका के साथ वन्यजीव संरक्षण भी आवश्यकीय है। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण के साथ लोगों की वनों पर निर्भरता कम हो और उनकी आजीविका भी चले, ऐसे प्रयास करने होंगे।

कार्यशाला में भा.व.संस्थान के डा.वीपी उनियाल के साथ कृषि, उद्यान, पशु पालन, पंचायतराज, पर्यटन, मत्स्य, शिक्षा आदि विभागीय अधिकारियों ने भी संबांधित किया।